

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—लंब 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1975/चैत्र 1, 1897

No. 69] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1975/ CHAITRA 1, 1897

इस भाग में विवर पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March 1975

G.S.R. 157(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, have received a report from the Governor of the State of Nagaland and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
- (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—
  - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
  - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the Reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;
  - articles 163 and 164;
  - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the Business of the Government of State;
  - articles 167 and 169;
  - clause (1) of article 174; articles 175, 176 and 177;
  - clause (c) of article 179 and the first proviso thereto;
  - articles 181, 188, 189, 193, 194, 196, 197 and 198;
  - clauses (3) and (4) of article 199; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
  - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State.
- (iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;
 

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 381 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;
- (iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI;  
The 22nd March, 1975.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,  
President.

[No. F.V/11013/1/75-S&P(DV)]

NEW DELHI;  
The 22nd March, 1975.

N. K. MUKARJI,  
Secretary.

## पूर्व मंत्रालय

श्रद्धिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1975

सं० का. नि. 157 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को नागालैंड राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त श्रद्धा सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

यतः अब मैं, सविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हैं;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित अनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या बांधनीय प्रतीत होते हैं; अर्थात्—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक कि मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य पाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है;

अनुच्छेद 167 और 169;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1); अनुच्छेद 175, 176 और 177;

अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 181, 188, 189, 193, 194, 196, 197, और 198;

अनुच्छेद 199 का खण्ड (3) और खण्ड (4); अनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं); अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जायगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ, क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जायगा;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से ले कर 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से ले कर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन उस सोमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एन्डद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा भानों उसके अन्तर्गत दूस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10वां) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा भानों यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली;

22 मार्च, 1975

फबरुवीन श्रीली अहमद,  
राष्ट्रपति।

[सं. का० पांच/11013/1/75—एस एंड पी (डी-V)]

निं० मुकर्जी, सचिव ।

## ORDER

New Delhi, the 22nd March 1975

**G.S.R. 158(E).**—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 22nd day of March, 1975 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Nagaland and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;  
The 22nd March, 1975.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,  
President.

[No. F.V/11013/1/75-S&amp;P(DV)]

NEW DELHI;  
The 22nd March, 1975.

N. K. MUKARJI,  
Secretary.

## [ग्रामेश]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1975

**सां का० भि० 158(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च, 1975 के बाइप्रैंस दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि नागालैंड राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के प्राधार पर स्वर्ण संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निवेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली;  
22 मार्च, 1975

फ़ब्रुअरी अली अहमद,  
राष्ट्रपति।

नई दिल्ली;  
22 मार्च, 1975

[सं० पांच/11013/1/75-एस एण्ड पी (डी-V)]  
नि० मुकर्जी, मंत्री।

